

TRUE VALUE

MARUTI SUZUKI



क्रिसमस को और भी खास
बनाएं **TRUE VALUE** के साथ!

अपनी कार आसानी से
खरीदें और बेचें!

TRUE VALUE

MARUTI SUZUKI



CELEBRATING

50 LAKH+

HAPPY FAMILIES



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play

यहाँ ऐप डाउनलोड करें।

छवियों का इस्तेमाल केवल उदाहरण मात्र है।

✓ ऐट-होम इवैल्यूएशन

✓ 376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

✓ ऑन-टाइम पेमेंट

✓ वेरिफाइड कार हिस्ट्री*

✓ आसान RC ट्रान्सफर

✓ 1 साल तक की वारंटी
और 3 फ्री सर्विस*

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

*नियम और शर्तें लागू। Verified Car History और Warranty केवल True Value प्रमाणित कारों पर लागू। निःशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। वाहन पर काला शीशा प्रकाश के कारण होता है।

TRUE VALUE
CERTIFIED

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtrdoot

चूरू, बुधवार 25 दिसम्बर, 2024

epaper.rashtrdoot.com



‘पनामा कैनाल अमेरिका द्वारा अमेरिकी पैसे से बनाई गयी’

ट्रम्प ने इस तर्क के साथ, पनामा कैनाल का संचालन व नियंत्रण हथियाने का इरादा जताया

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। अब तक उपलब्ध प्रारंभिक संकेतों से स्पष्ट है कि नया साल -2025- सभी देशों के लिए परेशानी भरा होने वाला है। भारत को आने वाले असमंजस भरे साल को समझदारी से निपटने के लिए हरसंभव कदम उठाना चाहिए।

डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नई कार्य व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें पनामा नहर, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, को फिर से अमेरिका के नियंत्रण में लाने की बात कही है। इसके साथ-साथ, कैनाल को अमेरिका का 51 वां राज्य बनाने की बात कहने के बाद, अब ट्रंप ने समुद्र के पार ग्रीनलैंड खरीदने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि विश्व शांति तथा फ्री वर्ल्ड के सरवाइवल के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए।

दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति की, अन्य देशों पर कब्जा करने की नीति, अन्य देशों की इस प्रवृत्ति को लगभग वैध बना देती है। इसे नए अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे अच्छा तोहफा मानकर, व्लादिमिर पुतिन ने, यूक्रेन के क्षेत्रों को छीनकर रूस का हिस्सा बनाने के अपने कदम के लिए यूरोप में समर्थन जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

■ जैसा कि विदित ही है, अमेरिका ने पिछली शताब्दी के प्रारंभ में, एक राजनीतिक आंदोलन को फण्ड करके व पनामा व कोलंबिया का विभाजन करवाया था तथा एक नये देश पनामा का जन्म हुआ था।

■ पनामा के स्वतंत्र होने के बाद, अमेरिका ने कैनाल का निर्माण किया था तथा काफी अर्से तक कैनाल पर अमेरिका का कंट्रोल था।

■ 1964 में पनामा में आंदोलन व अशांति के बाद कैनाल का कंट्रोल पनामा को सौंप दिया गया था।

■ अब ट्रम्प अमेरिका के व्यापार व ट्रेड के हित में कैनाल का नियंत्रण पुनः अपने हाथ में लेना चाहता है, क्योंकि ट्रम्प के अनुसार, पनामा बहुत भारी दाम वसूल कर रहा है कैनाल के उपयोग के लिये और यह अमेरिका के ट्रेडिंग व व्यापार के हित में नहीं है।

■ ट्रम्प की “मेक अमेरिका ग्रेट अगोन” (अमेरिका को पुनः महान बनाओ) नीति के अंतर्गत अमेरिका ग्रीनलैंड का भी अधिग्रहण करने की मंशा रखता है। जैसे अलास्का को रूस ने उन्नीसवीं शताब्दी में खरीदा था, उसी तरह अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है।

■ ट्रम्प के विस्तारवादी इरादों से प्रेरित होकर रूस ने भी यूरोप के छोटे-मोटे देशों पर कब्जा करने का इरादा अपनाया है।

पुतिन ने सार्वजनिक गलत सूचना सारकों को अस्थिर करने के भी प्रयास अभियान के साथ-साथ, यूरोप को कुछ शुरु कर दिए हैं। पुतिन के सहायक कह

चुके हैं कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, उसे समर्थन देने को लेकर यूरोप के देशों में भारी मतभेद हैं।

ट्रम्प के तथाकथित “मेक अमेरिका ग्रेट अगोन” प्लान में, पनामा कैनाल पर कब्जा करना सबसे भयावह व गंभीर है। ट्रम्प ने कहा है कि यह नहर, जो पहले अमेरिका के नियंत्रण में थी, अमेरिका के व्यापारिक व आर्थिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे फिर अमेरिका के नियंत्रण में लाना चाहिए।

पनामा के राष्ट्रपति होसे राउल मुलिने ने कहा है कि नहर का प्रत्येक मीटर पनामा का है और नहर और आस-पास की भूमि पर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्रम्प इससे हतोत्साहित नहीं हैं और उन्होंने युवा अमेरिकी कंजर्वेटिव्स के एक समूह से कहा है कि राष्ट्रपति कार्टर द्वारा पनामा सरकार को नहर पर नियंत्रण देने का कदम एक गलती थी।

डोनाल्ड ट्रम्प ने पनामा के लोगों के खिलाफ अभियान जारी रखा है। उनका कहना है कि पनामा नहर का उपयोग करने के लिए पनामा अमेरिका से बहुत अधिक शुल्क ले रहा है। ट्रम्प का दावा है कि पनामा नहर को अमेरिकी धन से बनाया गया था।

दोनों देशों के बीच उलझे हुए रिश्तों (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव नियमों में संशोधन, सुप्रीम कोर्ट पहुँची कांग्रेस

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। सी.सी.टी.वी. कैमरा तथा वैंबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की रिकॉर्डिंग जैसे इलैक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का सार्वजनिक निरीक्षण रोकने के लिए सरकार ने गत शुक्रवार को चुनाव नियमों में बदलाव किया था। एक अधिसूचना द्वारा किए गए इस संशोधन के बाद चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज अब जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने

■ केन्द्र सरकार ने सी.सी.टी.वी. और वैंबकास्टिंग फुटेज की जांच पर रोक लगाने के लिए गत शुक्रवार को चुनाव नियमों में बदलाव कर दिया था।

पोल पैलन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एकतरफा निर्णय लेकर “जल्दबाजी” में संशोधन किया है। उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट “नष्ट हो रही” चुनाव प्रक्रिया को बहाल करेगा। कांग्रेस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पार्टी ने “कंडक्ट ऑफ इलैक्शन रूलस, 1961”, में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती दी है तथा पूरा जोर दंग से कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है।

जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग, जिस पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेवारी है, ऐसे महत्वपूर्ण कानून में बदलाव करने का जल्दबाजी में एकतरफा निर्णय नहीं ले सकता।

जे.पी. नड्डा के आवास पर आज होगी एन.डी.ए. की मीटिंग

शाह की टिप्पणी के मुद्दे पर उग्र विपक्ष के खिलाफ जवाबी रणनीति तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई है

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विवाद के बीच, एन.डी.ए. के सभी पार्टनर बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के निवास पर इकट्ठे होकर मीटिंग करेंगे तथा विवाद की काट करने की रणनीति पर विचार करेंगे।

इस समय, भाजपा के सामने कई बड़े मुद्दे हैं। भाजपा को कुछ महत्वपूर्ण एवं निर्णायक मुद्दों पर एन.डी.ए. पार्टनर्स के साथ मित्रता के माहौल में एक एकीकृत रणनीति की आवश्यकता है। इन मुद्दों में शामिल हैं- “एक राष्ट्र एक चुनाव” विधेयक तथा “वक्फ संशोधन” विधेयक। ये दोनों ही विधेयक विस्तृत संवीक्षा के लिये संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे हुये हैं।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में लोकसभा की संरचना बदली हुई है। इस वजह से भाजपा नेतृत्व छोटे-बड़े सभी मुद्दों पर अपने सभी मित्र दलों को साथ लेकर चलने की जरूरत के विषय में बहुत सावधानी से काम लेता प्रतीत हो रहा है। भाजपा ज्यादा सचेत खासतौर से इसलिये भी है क्योंकि विपक्षी नेता अम्बेडकर पर शाह की टिप्पणी के सम्बंध में भाजपा और एन.डी.ए. पार्टनरों के बीच दारार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

■ प्र.मंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल को लोकसभा में समीकरण बदल गए हैं। अब घटक दलों पर निर्भरता बढ़ गई है। यही कारण है कि भाजपा एन.डी.ए. की बैठक बुला रही है, ताकि घटक दलों को छिटकने से रोका जा सके।

■ भाजपा को “एक राष्ट्र एक चुनाव बिल” और वक्फ संशोधन बिल पर सहयोगी दलों की सख्त जरूरत है।

■ इसके अलावा भाजपा को आशंका है कि शाह की अंबेडकर संबंधी टिप्पणी पर कहीं सहयोगी दल विपक्षी दलों की बातों में न आ जाएं।

पूर्व प्रधानमंत्री तथा भाजपा के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी की 100 वीं वर्षगांठ वाले दिन हो रही इस मीटिंग में, भाजपा गठबन्धन पार्टनरों के सम्मुख एक समझौता प्रस्ताव रखने की तैयारी में दिखाई दे रही है। सूत्रों का कहना है कि ऐसी संभावना है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिये, भाजपा अपने गठबन्धन पार्टनरों - जनता दल यूनाइटेड (जे.डी.यू.) तथा चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) को कुछ सीटों की पेशकश करेगी। भाजपा के लिये बिहार की इन दोनों पार्टियों को प्रसन्न रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के विधानसभा अगले वर्ष ही होने हैं।

जहाँ प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के प्रथम दो कार्यकालों में एन.डी.ए. की मीटिंग बहुत की कम हुई थीं, वहीं, भाजपा नेतृत्व इस बार, तर्कसंगत कारणों से, इस प्रकार की मीटिंगें करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। अभी -अभी समाप्त हुये संसद के शीतकालीन सत्र में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एन.डी.ए. पार्टनरों से कहा था कि बेहतर समन्वय बनाये रखने के लिये हर महीने मीटिंग हुआ करेगी। इस वर्ष हुये लोकसभा चुनावों में, अपने बलबूते पर लोकसभा में बहुमत लाने में भाजपा की असफलता मानसिक रूप से पार्टी को सहज नहीं होने दे रही, जबकि अभी हाल ही में, उसने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते हैं। विपक्ष, लोकसभा में अच्छे संख्याबल के चलते, भाजपा के सामने चुनौतियाँ खड़ी करता आ रहा है। अगर आगामी महीनों और वर्षों में कुछ राज्यों में भाजपा को हार का मुँह देखा पड़े, तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जायेगी।

बेलगांव में 26 दिसम्बर 1924 को महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे

पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया, सभी जिलों में कांग्रेस सप्ताह भर आंदोलन करेगी, फिर राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन देकर शाह के इस्तीफे की मांग करेगी

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

बेलागावी (अब बेलगाँव) में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी के चुनाव का स्मरणोत्सव मनाने के उद्देश्य से, कांग्रेस बेलगाँव में कांग्रेस वार्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) की विस्तृत मीटिंग आयोजित कर रही है। इस ऐतिहासिक मीटिंग में करीब 200 पार्टी-नेता शामिल होंगे।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि 26 दिसम्बर को अपराह्न 2:30 बजे बेलगाँव के महात्मा गांधी नगर में “नव सत्याग्रह बैठक” होगी। इससे एक दिन बाद 27 दिसम्बर को वहाँ “जय बापू, जय भीम, जय संविधान” सभा होगी, जिसमें लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि वस्तुतः यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक

■ बेलगाँव में कांग्रेस कार्य समिति की नव सत्याग्रह बैठक हो रही है। इसके अगले दिन “जय बापू, जय भीम, जय संविधान” रैली होगी।

■ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि बेलगाँव का कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक महत्व है। सौ साल पहले 26 दिसम्बर 1924 को यहीं महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और सेवा दल की शुरुआत भी यहीं से हुई थी।

अविस्मरणीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जब पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपने महान नेता महात्मा गांधी की अध्यक्षता के 100वें वर्ष का सुखद स्मरणोत्सव मनायेगी।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी ने 100 वर्ष पूर्व बेलगाँव से ही सत्याग्रह की घोषणा की थी और 100 वर्ष बाद, उसी दिन कांग्रेस “नव सत्याग्रह” का प्रस्ताव पेश करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस

सांसद और पार्टी कार्यकर्ता 27 दिसम्बर को वहाँ उपस्थित होंगे।

उन्होंने कहा कि यह मीटिंग, ढाई साल पहले उदयपुर में हुये चिन्तन शिविर की तरह, एक ऐतिहासिक मीटिंग का रूप लेने जा रही है। ज्ञातव्य है कि “भारत जोड़ो यात्रा” का विचार उसी चिन्तन शिविर की देन था।

पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में एक (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बने

नई दिल्ली, 24 दिसंबर। भारत के राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियों की हैं। डॉ. अरिफ बाबू कंभरपति, जो मिजोरम के राज्यपाल थे, अब ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं।

पूर्व सेना प्रमुख, जनरल वीके सिंह को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के राज्यपाल होंगे।

बिहार के राज्यपाल राजेंद्र

■ पांच राज्यों के राज्यपाल बदले।

विश्वनाथ अलंकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं, केरल के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के राज्यपाल होंगे। इसके अलावा, अजय कुमार भट्टाला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों के साथ, संबंधित राज्यों में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव आया और राज्यपाल नए पदभार संभालेंगे।

विवाहिता बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश बरकरार

जयपुर, 24 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विवाहिता बेटी को पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति का हकदार मानने वाले एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर राज्य सरकार

■ हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को कायम रखते हुए इसके खिलाफ दायर सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।

को अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा राहुल गांधी ने “राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग” के सदस्यों और अध्यक्ष के चयन पर अपना विरोध दर्ज करा दिया था। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष पद के लिये जस्टिस रोहिन्टन फली नरीमन तथा जस्टिस कुट्टियिल मैथ्यू जोसफ के नाम प्रस्तावित किये थे। लेकिन विपक्ष के सुझाव की उपेक्षा करते हुये, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने एन.एच.आर.सी. के नये अध्यक्ष पद के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी. रामासुब्रमन्यम को नियुक्त कर दिया है। एन.एच.आर.सी. के अध्यक्ष एवं

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर विरोध जताते हुए राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने हमारे प्रस्ताव पर विचार तक नहीं किया

सदस्यों के चयन के लिये चयन समिति की मीटिंग 18 दिसम्बर को संसद भवन में हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस हाई पावर कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल थे- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।

खड़गे और राहुल का आरोप है कि विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करने तथा सामूहिक निर्णय सुनिश्चित करने

■ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो चयन समिति के सदस्य हैं, ने कहा कि सरकार ने पहले ही तय कर रखा था किसे अध्यक्ष बनाना है।

■ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति के सदस्य हैं, गृह मंत्री शाह, लोकसभा स्पीकर बिड़ला, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे।

■ केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. रामासुब्रमन्यम को नियुक्त किया है।

के बजाय, कमेटी ने नाम को अंतिम रूप देने के लिये संख्यात्मक बहुमत पर भरोसा किया तथा मीटिंग के दौरान उठाये गये वाजिब सरोकारों तथा परिप्रेक्ष्यों पर ध्यान ही नहीं दिया।

असहमति की टिप्पणी में कहा गया कि मैरिट निश्चित रूप से प्राथमिक शर्त होती है, लेकिन राष्ट्र की क्षेत्रीय, जातीय, समुदाय संबंधी तथा धार्मिक विविधता को दर्शाने वाला संतुलन बनाये रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

अठारह दिसम्बर को दिये गये

विरोध सूचना टिप्पणी (डिसेन्ट नोट) में कहा गया, “अंत में, आज की मीटिंग में चयन समिति द्वारा अपनाया गया विचार-विमर्श पर ध्यान नहीं देने का तौर-तरीका अत्यधिक दुःखद है। एन.एस.आर.सी. की विश्वसनीयता तथा प्रभावकारिता, विविधतापूर्ण एवं समावेशी होने, जो भारत के संविधान की प्रकृति को परिभाषित करते हैं, की सामर्थ्य पर निर्भर होती है।”

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज रामासुब्रमन्यम को एन.एच.आर.सी. का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।

प्रियांक कानुनगो तथा डॉ. जस्टिस विद्युतरंजन सारंगी (रिटायर्ड) एन.एच.आर.सी. के सदस्य नियुक्त किये गये।

लिए भारत को आकर्षक विकल्प बनाने का लक्ष्य है।

भारत सरकार बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है और अर्थव्यवस्था को ज्यादा उदर बनकर अमेरिकन निवेश को आकर्षक बनाने की प्रतिबद्धता का संकेत दे रही है।

व्यापारिक असंतुलन को ठीक करने के लिए भारत अमेरिका से हर साल 5 से 10 अरब डॉलर की लिक्विडिटी नैचुरल गैस और रक्षा उपकरणों का आयात करने पर विचार कर रही है। इससे द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे और भारत की इस इच्छा का भी संकेत मिलता है कि वह प्रतिस्पर्धी व्यापार में दिलचस्पी रखता है।

भारत का लक्ष्य अमेरिका की आपूर्ति शृंखला से गहरा जुड़ाव रखना और दोनों देशों के बीच परस्पर आर्थिक निर्भरता को बढ़ाना है। ये प्रोत्साहन देना भारत उन अमेरिकी निर्माताओं को (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

कार और बस की आमने-सामने भिड़ंत

करोली, 24 दिसम्बर (निस)। गंगापुर सड़क मार्ग पर सलेमपुर गांव के पास स्विचट डिजायर कार और बस में आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार 5 महिला-पुरुषों की मृत्यु हो गई। बस में सवार करीब डेढ़ दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। जानकारी के

■ गंगापुर रोड पर सलेमपुर गांव के पास हुए इस हादसे में कार में सवार 5 महिला-पुरुषों की मौत हो गई, डेढ़ दर्जन बस यात्री घायल हो गए।

अनुसार, करोली की ओर से कार गंगापुर की तरफ जा रही थी। प्राइवेट बस गंगापुर से करोली की तरफ आ रही थी। गंगापुर और सलेमपुर के बीच स्थित छात्रवास के पास दोनों वाहन आमने-सामने से टकरा गए। हादसे में कार चालक सहित (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने बाबा साहब का किया अपमान, भाजपा ने दिया सम्मान : भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सत्ता लोलुप पार्टी है, केवल सत्ता हासिल करना उसका उद्देश्य है



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा से बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का रहा है और आज यह पार्टी उनके नाम पर हक मांगने का ढोंग कर रही है।

जयपुर, 24 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा से बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने और उनका मजाक उड़ाने का रहा है और आज यह पार्टी उनके नाम पर हक मांगने का ढोंग कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस को अपने नेताओं और जवाहर लाल नेहरू द्वारा बाबा साहब

डॉ. अंबेडकर के अपमान के लिए पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कारण ही देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उसने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के त्यागपत्र को जनता के सामने क्यों नहीं आने दिया? उन्होंने कहा कि नेहरू ने एडविना मार्टिन्डेल को भी पत्र लिखकर बाबा

साहब अंबेडकर के कैबिनेट में न रहने पर खुशी जाहिर की थी। ऐसी सोच वाली कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब के नाम पर झूठ की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को 1952 के लोकसभा चुनाव और 1954 के उपचुनाव में हराया। इस पार्टी के शासन में उन्हें भारत रत्न तक नहीं दिया गया। देशभर में नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी के नाम पर सैकड़ों स्मारक, अस्पताल और

■ भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा सांसदों से धक्का-मुक्की करना बहुत शर्मनाक है।

सड़कों के नाम रख दिए गए, मगर बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनने दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता लोलुप बताते हुए कहा कि यह पार्टी सत्ता के बिना नहीं रह सकती। कांग्रेस नेताओं का प्रयास रहता है कि येन-केन-प्रकारेण सत्ता हासिल करे, फिर चाहे झूठ, धर्म या जातिवाद की राजनीति ही क्यों न करनी पड़े। केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आई, तो दिल्ली में अंबेडकर सेंटर बनकर तैयार हुआ। मोदी की सरकार ने लंदन में जहां बाबा साहब रहे थे, वहां उनकी एक स्मृति बनवाई, दिल्ली में उनके निवास स्थान पर स्मृति स्थापित की, नागपुर की दीक्षा भूमि और मुंबई की चैत्य भूमि में भी स्मृतियां बनाईं। कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही, लेकिन उसने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, जबकि भाजपा समर्थित सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया।

भजनलाल ने कहा कि राहुल गांधी ने सांसदों से धक्का-मुक्की की, जो बेहद शर्मनाक कृत्य है।

'पनामा कैनाल अमेरिका द्वारा अमेरिकी पैसे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का इतिहास शांति और सद्भाव से भरा हुआ नहीं है। अमेरिका ने पनामा के गठन के लिए राजनीतिक आंदोलन आयोजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप पनामा कोलंबिया से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। पनामा के कोलंबिया से स्वतंत्र होने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने नहर का निर्माण किया और उसके

बाद पिछली सदी से लेकर 1964 तक नहर पर अमेरिकी नियंत्रण रहा इसके बाद, अमेरिकियों के लिए विरोध शुरू हुआ। लंबी वार्ताओं के बाद नहर पर संयुक्त नियंत्रण स्थापित हुआ, और 1999 में स्वामित्व और संचालन पनामी लोगों को सौंप दिया गया।

अब, डोनाल्ड ट्रम्प इसे फिर से वापस लेना चाहते हैं, ताकि यह अमेरिका के व्यापार और रणनीतिक हितों

के लिए उपयोगी हो सके। लेकिन इससे भी ज्यादा चौकाने वाला है ट्रम्प का ग्रीनलैंड पर स्वामित्व का दावा, जो दुनिया के एकदम दूसरी ओर स्थित है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिकी अस्तित्व और रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। वे इसे अमेरिका द्वारा 19 वीं सदी में रूस से खरीदे गये अलास्का की तरह खरीदना चाहते हैं।

कोलकाता हत्याकांड: एफ.एस.एल. के अनुसार, सेमिनार रूम में रेप व हत्या नहीं हुई

कोलकाता, 24 दिसंबर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसी साल 9 अगस्त को अस्पताल की चौथी मंजिल पर बने सेमिनार रूम से जूनियर डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। वही, अब इस रूम में बलात्कार और हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं। केंद्रीय फोरेंसिक अनुसंधान प्रयोगशाला (सी.एफ.एस.एल.) की रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल पर मृतका और हमलावर के बीच हाथापाई और मारपीट के कोई निशान नहीं मिले हैं। आरजी कर अस्पताल मामले की सीएफएसएल रिपोर्ट हाल ही में जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपी गई है।

सी.एफ.एस.एल. की रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि सेमिनार रूम में नौले गढ़े पर मृतका और हमलावर के बीच संभावित हाथापाई के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

कार और बस की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

5 जनों की मृत्यु हो गई। कार मध्यप्रदेश के नम्बर की बताई जा रही है। समाचार लिखे जाने तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।

करौली चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामकेश मीणा ने बताया कि दुर्घटना की सूचना जिला कलेक्टर से प्राप्त हुई थी। एंबुलेंस के जरिए मृतकों को अस्पताल लाया गया। 4 जनों को चिकित्सक ने मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए मूर्दाघर में रखवा दिया है।

उन्होंने बताया कि एक महिला, जो गंभीर रूप से घायल हुई थी, को गंगापुर ले गए, जहां अस्पताल पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई।

डॉक्टर रामकेश मीणा ने बताया कि बस में सवार यात्रियों में से करीब डेढ़ दर्जन महिला पुरुष घायल हुए हैं, जिनको करौली चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बस में सवार लोगों ने बताया कि एक ब्रेकर था, जिस से कार चालक का संतुलन बिगड़ने से कार बस के सामने आ गई और टकरा गई।

पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

जयपुर, 24 दिसंबर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर प्रथम ने आपसी विवाद में पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, पीठासीन अधिकारी राजेश गोरा ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, अभियुक्त के खिलाफ अपनी बेटी से सालों तक दुष्कर्ष करने को लेकर पाँक्सो कोर्ट में केस चल रहा है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त के बेटे ने 1 दिसंबर, 2020 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह दोपहर को बाजार गया था। शाम को वापस आने पर उसके भाई-बहन घर में थे और बेडरूम का गेट बंद था। जब उसने अपने पिता से मां के बारे में पूछा तो उन्होंने मां के हरिद्वार जाने की बात कही और मां को तलाश करने के नाम पर उसे साथ लेकर बस स्टैंड चले गए। इसके बाद, पिता वहां से कहीं चले गए। जब वह वापस आया तो भाई ने बताया कि मां की लाश पलंग में मिली थी और मामा उसे

■ अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया। ज्ञातव्य है कि उक्त आरोपी पर सालों तक पुत्री से दुष्कर्ष करने का आरोप भी है, जिसका केस पाँक्सो कोर्ट में चल रहा है।

लेकर अस्पताल गए हैं। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता बेटे ने पुलिस रिपोर्ट से अलग बयान दिए। हालांकि अदालत के सामने आया कि अभियुक्त की बेटी ने पुलिस को बयान दिए थे कि उसके पिता ने करीब छह साल तक उसके साथ दुष्कर्ष किया था और उसका मामला पाँक्सो कोर्ट में चल रहा है। इसकी जानकारी उसकी मां को हो गई थी और इसके कारण दोनों में झगडा होता था।

बेलगांव में 26 दिसम्बर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सप्ताह के विरोध-प्रदर्शन आयोजित किये तथा उसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू को एक ज्ञापन दिया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किये गये बाबासाहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर, उनके इस्तीफे की माँग की गई।

वेणुगोपाल ने कहा, "देश यह अपेक्षा कर रहा है कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर क्षमा याचना करेंगे, यह देश को आशा और अपेक्षा थी, लेकिन क्या हुआ। इसके बाद भी, वे दिन-पर-दिन अंबेडकर जी की विरासत का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन वे सर्वोच्च न्यायालय को नष्ट करने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चुनाव-प्रक्रिया की पूरी तरह से जड़ काट रहे हैं। वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की काट-छाँट कर रहे हैं। यही कारण है कि हम बेलगांव में विस्तृत-चर्चा करेंगे तथा इस मुद्दे का निश्चित रूप से मजबूत "फॉलो अप" किया जायेगा।"

जयपुर रमेश ने कहा कि बेलगांव का एक ऐतिहासिक महत्व है। इसका कारण केवल यही नहीं कि महात्मा गांधी

100 वर्ष पहले यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, एक कारण यह भी है कि 26 दिसम्बर, 1924 को डॉ. एन.एस. हार्दिकर ने सेवा दल का शुभारंभ यहीं से किया था। वेणुगोपाल ने कहा कि बेलगांव की सी. डब्ल्यू.सी. मीटिंग से राहुल गांधी की "नव सत्याग्रह यात्रा" का शुभारंभ होगा, उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में साल-भर चलने वाले कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श एवं निर्णय होगा।

उन्होंने कहा, पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है- भाजपा की योजना से लड़ना तथा अमित शाह के इस्तीफे पर जोर देना। उन्होंने कहा कि भाजपा रोजाना मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रणनीति गुरुवार की संसद की सी.सी.टी.वी. फुटेज के लिये दबाव बनाने की है।

वेणुगोपाल ने यह घोषणा भी की कि बेलगांव में सी.डब्ल्यू.सी. पार्टी के संगठनात्मक ढाँचे तथा 2025 में संगठन में होने वाली फेरबदल के बारे में निर्णय लेगी।

विवाहिता बेटी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

मामले से जुड़े अधिकता एस.जे. मूथा ने बताया कि एकलपीठ की याचिकाकर्ता मंजू लता के पिता पुलिस लाइन, बारां में ए.एस.आई. पद पर कार्यरत थे। इयूटी के दौरान 20 मार्च 2016 को उसके पिता की मौत हो गई। परिवार में अन्य कोई सक्षम आश्रित नहीं होने पर याचिकाकर्ता की मां ने मई 2016 में अपनी बेटी को पुत्रक पति के आश्रित के तौर पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसका आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि बेटी विवाहित है और वह अनुकंपा नियुक्ति की पात्र नहीं है। मंजू लता ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना और राज्य सरकार को उसे नियुक्ति देने के लिए कहा, लेकिन राज्य सरकार ने आदेश की पालना नहीं की, जिसे याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका के जरिए चुनौती दी। वहीं, राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की। अब खंडपीठ ने भी एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए, राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है।

भारत अमेरिका के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है जो चीन से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रम्प ने सभी आयातों पर 10 से 20 प्रतिशत का बेसलाइन शुल्क प्रस्तावित किया है और जो देश डॉलर पर निर्भरता घटाने जैसे अन्य अनुचित कार्यों में संलग्न होंगे, उन पर शुल्क बढ़ाया भी जा सकता है। इसके तहत कैनडा और मैक्सिको पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने और चीन पर दस प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। व्यापारिक नीतियों की अनिश्चितता अंतर्राष्ट्रीय निवेश को हतोत्साहित कर सकती है। आर्थिक विकास को रोक सकती है, क्योंकि व्यवसायों को बदलते नियमों के अनुकूल योजना बनाने में मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया जैसे देश संभावित अमेरिकन शुल्कों को लेकर चिंतित हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इन देशों की राजनीतिक अस्थिरता अमेरिका को जवाब देने की उनकी क्षमता को और कमजोर कर सकती है।

स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर उत्थान आयुष्मान भारत, आयुष्मान राजस्थान

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण

अनेक रोगों का निराकरण

समझदारी दिखाएँ!

अपने बच्चे का सम्पूर्ण टीकाकरण करवाएँ

इन 11 बीमारियों से बचाव हेतु बच्चों के टीके अवश्य लगवाएँ

• पोलियो • निमोनिया • टीबी/तपेदिक • टिटनेस • हैपेटाइटिस-बी • मेनिनजाइटिस • गलघोंटू/डिप्थीरिया • खसरा • रूबैला • काली खांसी • रोटा वायरस दस्त

U-WIN App में स्वयं रजिस्टर करें व डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

सभी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित दिवस पर लाभार्थी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीके लगाये जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र अथवा स्वास्थ्य कार्मिक से सम्पर्क करें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (आई.ई.सी.), राजस्थान

एक वर्ष परियोजना उत्कर्ष

गोविन्द विहार

आवासीय योजना

(गोविन्दपुरा - रोपाड़ा, हैरिटेज सिटी) जोन-10
(राज रजिस्ट्रेशन नं. RAJ/P/2023/2587)

202 भूखण्डों का लॉटरी से आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ

आवेदन की प्रारम्भ तिथि : 25 दिसंबर 2024
आवेदन की अन्तिम तिथि : 24 जनवरी 2025
लॉटरी की तिथि : 05 फरवरी 2025

आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु
जयपुरा की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in अथवा
ई-मित्र कियोस्क केंद्रों पर उपलब्ध हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहर नाल रोड मार्ग, जयपुर-302004